



८७

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राप्तिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 1992/भाद्रा 6, 1914

No. 163]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 1992/BHADRA 6, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पर्यावरण और बन मंत्रालय  
नई दिल्ली 28 अगस्त, 1992

निम्नलिखित विषयों के  
सचिव, भारत सरकार

## संकल्प

सं. ८-५९०।।।/।।।/१।।।/१११ पी. II:—ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाल ही में बंजर भूमि विकास विभाग बनाया जाने और राष्ट्रीय परियोगी भूमि विकास बोर्ड को इस विभाग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप पर्यावरण और बन मंत्रालय में राष्ट्रीय बनाकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. राष्ट्रीय बनाकरण पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड का गठन भूमिका और कार्य नाथे नामों में दिए गए हैं:—

गठन

पदेन सदस्य

- (1) केन्द्रीय पर्यावरण और बन मंत्री-----
- (2) मध्यस्थानारा नामित किया जाएगा
- (3) सदस्य, योजना आयोग पर्यावरण प्रभारी

अध्यक्ष  
उपाध्यक्ष  
सदस्य

(4) ग्रामीण विकास	सदस्य
(5) कृषि अनुबंधान और जिता	सदस्य
(6) व्यवस्था	सदस्य (वित्त)
(7) विज्ञान और प्रौद्योगिकी	सदस्य
(8) कृषि और सहकारिता	सदस्य
(9) पशु पालन और दुध उत्पादन	सदस्य
(10) बंजर भूमि विकास	सदस्य
(11) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड	सदस्य
(12) बन महानिरीक्षक, पर्यावरण और बन मंत्रालय	सदस्य
(13) मध्यस्थान, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	सदस्य

## नामित सदस्य

(14) संसद सदस्य (लोक सभा और

15) राज्य सभा से एक-एक)

(16) बनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास

(22) कार्यकलापों से जुड़ी स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी

संस्थाओं आदिकों आदि के प्रतिनिधि

(सात से अधिक नहीं)

सदस्य

सदस्य

(23-27) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (पांच से अधिक

नहीं) जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के में

नीचे के नहीं होंगे

भदस्य

## सदस्य सचिव

(28) सचिव (पर्यावरण और वन)

सदस्य सचिव

## भूमिका और कार्य

राष्ट्रीय बनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड देश में बनीकरण, बृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा। अवक्रमित वन क्षेत्रों तथा बन क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों, आभ्यारणों व अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास की भूमि और पर्यावरणी हिमालय, अरावली पहाड़ियों, पश्चिमी घाटों आदि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों के पुनरुत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास के लिए योजनाएं तैयार करने में बोर्ड निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(क) योजनाबद्ध आयोजना तथा कार्यव्यवस्था के जरिए लागत प्रभावी तरीके से अवक्रमित वन क्षेत्रों और उनके आस-पास की भूमि के पारिस्थितिकीय सुधार के लिए कार्यव्यवस्था तैयार करना,

(ख) पारिस्थितिकीय सुरक्षा और आमोंण समुदायों की ईंधन लकड़ी वारे तथा अन्य जलरसों को प्रोत्ता करने के लिए प्राकृतिक पुनरुत्पादन अथवा समृद्धि उपायों से देश को बनाढ़ादित करना।

(ग) ईंधन लकड़ी, चारे, इमारती लकड़ी और बनोपज की मांग को पूरा करने के लिए अवक्रमित वनों और उनके आस-पास की भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारे, इमारती लकड़ी और बनोपज के दृष्ट उदान।

(घ) अवक्रमित वन क्षेत्रों और उनके आस-पास की भूमि के पुनरुत्पादन और विकास हेतु नई और उचित प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिए अनुसंधान प्रायोजित करना और अनुसंधान नतीजों का विस्तार करना,

(ङ) स्वैच्छिक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्यों की मदद से बनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आम जागरूकता पैदा करना जन-आयोलन तैयार करना तथा अवक्रमित वन क्षेत्रों तथा उनके आस-पास की भूमि के सहभागी और सन्तु प्रबंध को बढ़ावा देना,

(च) बनीकरण, बृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास की कार्य योजनाओं का समन्वय और अनुबोधन करना, और

(छ) देश में बनीकरण, बृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय करना।

## आदेश

आदेश है कि इस संकल्प को एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह सभी आदेश है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

वित्त शंकर, अपर सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT &amp; FORESTS

New Delhi, the 28th August, 1992

## RESOLUTION

No. A-59011/1/91/P.II.—Consequent upon the formation of the new Department of Wastelands Development in the Ministry of Rural Development and the transfer of the National Wastelands Development Board (NWDB) to that Department, it has been decided to set up the National Afforestation and Eco-Development Board (NAEB) in the Ministry of Environment and Forests.

2. The composition, role and functions of NAEB are given in the following paragraphs :

## COMPOSITION :

## Ex-officio Members.

- (1) Union Minister for Environment and Forests. —Chairman.
- (2) To be nominated by the Chairman. —Vice Chairman.
- (3) Member, Planning Commission Incharge of Environment. —Member.

Secretaries to the Government of India in the Departments of :

- (4) Rural Development —Member.
- (5) Agricultural Research & Education —Member.
- (6) Expenditure —Member (Finance).
- (7) Science & Technology —Member.
- (8) Agriculture & Cooperation —Member.
- (9) Animal Husbandry & Dairying —Member.
- (10) Wastelands Development .. Member.
- (11) Member Secretary, National Land Use and Conservation Board —Member.
- (12) Inspector General of Forests, MOEF —Member.
- (13) Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development —Member.

## Nominated Members :

- (14—15) Members of Parliament (one each from the Lok Sabha and the Rajya Sabha) —Member.
- (16—22) Representatives (not exceeding seven) of Voluntary Agencies, Cooperative Institutions, Tribals, etc. connected with afforestation and eco-development activities. —Member.
- (23—27) Representatives of State Governments (not exceeding five) not below the level of Secretary of State Government. —Members.

## Member Secretary :

- (28) Secretary (Environment & Forests) Member-Secretary.

**ROLE AND FUNCTIONS :**

The National Afforestation and Eco-Development Board will be responsible for promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development activities in the country. Special attention will be given to the regeneration of degraded forest areas and lands adjoining forest areas, national parks, sanctuaries and other protected areas as well as the ecologically fragile areas like the Western Himalayas, Aravallis, Western Ghats, etc. In drawing up the plans for afforestation and eco-development, the Board will ensure the following :—

- (a) Evolve mechanisms for ecological restoration of degraded forest areas and adjoining lands through systematic planning and implementation, in a cost effective manner;
- (b) Restore through natural regeneration or appropriate intervention the forest cover in the country for ecological security and to meet the fuelwood, fodder and other needs of the rural communities;
- (c) Restore fuelwood, fodder, timber and other forest produce on the degraded forest and adjoining lands in order to meet the demands for these items;

- (d) Sponsor research and extension of research findings to disseminate new and proper technologies for the regeneration and development of degraded forest areas and adjoining lands;
- (e) Create general awareness and help foster people's movement for promoting afforestation and eco-development with the assistance of voluntary agencies, non-government organisations, Panchayati Raj institutions and others and promote participatory and sustainable management of degraded forest areas and adjoining lands;
- (f) Coordinate and monitor the Action Plans for afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development; and
- (g) Undertake all other measures necessary for promoting afforestation, tree planting, ecological restoration and eco-development activities in the country.

**ORDER**

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VINAY SHANKAR, Addl. Secy.

